DEPARTMENT OF ENVIRONMENT (SHRI DIGVIJAY SINH) :

I beg to lay on the Table a copy of the Wild Life (Protection) Licensing (Additional Matter for Consideration) Rules, 1983 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 328(E) in Gazette of India dated the 13th April, 1983, under sub-section (2) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972. [Placed in Library. *See* No. LT-6555/83].

12.12 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

> "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1983, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th April, 1983, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : Mr. Stephen is here. He should say something. Mr. Stephen should defend himself. I have got some charges against him....**

MR. SPEAKER : I have not allowed him.

12.13 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Fifty-ninth Report

SHRI G. LAKSHMANAN (Madras North) : I beg to present the Fifty-ninth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Collection of a large sum of Money by Messers Lohia Machines Ltd., Kanpur as Advance for Booking of Vespa-XE Scooters

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं अविलम्वनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"मैसर्स लोहिया मशीनज लिमिटेड, कानपुर द्वारा, वैस्पा-एक्स० ई० स्कूटरों की बुकिंग के लिए पेशगी रकम के रूप में बड़ी भारी धन-राशि एकत्र किए जाने, हालांकि उसकी फैक्टरी अभी तैयार भी नहीं हुई है तथा फर्म का लाइसेंस समाप्त करने की मांग के समाचार की ओर"।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर को अन्य के साथ-साथ एक लाख दुपहियों के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है। स्कूटरों और मोपेडों का निर्माण करने के लिए उन्होंने इटली की मैसर्स पियागिओ के साथ सहयोग किया है।

**Not-recorded.

2. कुछ महीने पहले कम्पनी ने स्कूटरों की बुकिंग के लिए प्रति गाड़ी 500 रुपए की दर से भावी खरीददारों से जमाराशियां आमंत्रित की थीं। उन्होंने बताया था कि इन बुकिंगों पर जमाकर्त्ताओं को 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा। कम्पनी से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार लगभग 21 लाख की बुकिंग हुई है और इस प्रकार इकट्ठी की गई राशि लगभग 105 करोड़ रुपए हैं। जमा राशियों का प्रश्न पहले भी सदन में उठाया गया है जिसमें माननीय सदस्य, श्री अशफाक हुसैन द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न भी शामिल है। मैंने बताया था कि लोहिया मशीन्स सहित मोटरगाड़ी-निर्माताओं द्वारा ली गई जमाराशियों के संबंध में सम्पूर्ण मामले की जांच करने और सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी। समिति का गठन किया जा चुका है और इसने अपना काम आरम्भ कर दिया है।

3. कम्पनी ने सूचित किया है कि उसने औद्योगिक लाइसेंस व विदेशी सहयोग करार के कार्यान्वियन के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उसने कारखाने की इमारत का निर्माण भी प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी द्वारा मशीनों की खरीद के लिए क्रयादेश भी दे दिए गए हैं। कम्पनी ने बताया है कि नवम्बर, 1983 तक स्कूटरों का निर्माण प्रारम्भ होने की संभावना है।

4. जहां तक उनके द्वारा सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के लिए कम्पनियों द्वारा जमा-राशियों को लेने का सम्बन्ध है, यह एक सामान्य वाणिज्यिक प्रथा रही है।

श्री मनी राम बागड़ी : उद्योग मंत्री जी ने जो जवाब दिया है इस पर सवाल करने से पहले एक बात जो मेरी कमजोरी की है, कहना चाहता हूं। लोहिया शब्द इस फर्म के साथ जोड़ा गया है। इससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। इस देश में जो तपस्वी और त्यागी लोग हुए हैं जैसे गांधी जी, जय प्रकाश जी, लोहिया जी, उनके नाम लुटेरों के साथ जोड़े जाएं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है (इंटरप्शंज)। सरकार की नीति और नीयत का कर्म से पता लगता है।

एक वाक्य कहूंगा कि देश में कल कारखाने की जरूरत सबसे ज्यादा कमजोर, निर्बल और निर्धन आदमी के साधनों को बनाने के लिए होनी चाहिए। अगर कारखानें बने तो सबसे पहले साइकिल के लिए हों, न कि कार, मोटर साइकिलों के वास्ते। यह तो नीयत और नीति है। अध्यक्ष महोदय, डाकू शायद मानसिंह सबसे बड़ा हुआ है उसको 2, 3 लाख रु० के डाके के लिए पिस्तौल और बन्दूक दिखानी पड़ी और तकलीफ उठानी पड़ी। लेकिन इस सरकार के राज्य के अन्दर आप लोग देखियेगा कि इस कम्पनी के मालिक ने न पिस्तौल दिखाई है, न तकलीफ उठायी है, केवल चालाकी या अखबार में लिखा पढ़ी कर, या किसी नेता या नीति का सहारा लेकर करोड़ों रु० का डाका डाला है। न जमीन, न कारखाना, कोई भी चीज बनी हुई नहीं है, और न कोई चीज देने की बात है कि कब स्कूटर देंगे। अगर हेराफेरी कर के चालाकी करके, सबको चाल में फंसा कर लोगों का पैसा इकट्ठा करके और उनके ब्याज का शोषण करे तो यह धोखेबाजी है और लम्बे रास्ते पर इसको डाका भी कहा जा सकता है। जैसे बयान में लिखा है कि 9 परसेंट ब्याज देगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है आजकल? जब लोगों ने 500 रुपया सेक्योरिटी जमा करने के लिए दर्खास्त दी उस वक्त इसके पास न जमीन, न कोई मकान था, न कल कारखाने की मशीनें थीं और न उसके पास कोई चीज थी। और यह पैसा इकट्ठा करने के बाद कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के बाद लौटरी निकालनी चाहिये थी। और लाटरी का सिस्टम भी कितनी चालाकी का रखा है कि 25 परसेंट उन लोगों को दिया जाएगा जो डिबेंचरधारी होंगे। बगैर असैट के डिबेंचर कैसे हो सकता है। 50 परसेंट टर्नवाइज होगा और 25 परसेंट लाटरी से दिये जायेंगे हर तीसरे महीने। यानी अगर एक

लाटरी निकाली जाए और सीरियल नम्बर से हो तो बाकी के लोग अपना पैसा निकाल लेंगे क्योंकि इस तरह से 50 साल में भी लोगों का नम्बर नही आयेगा ।

लेकिन 3 महीने वाली शर्त इसीलिए रखी है कि लोग जूए के सिस्टम से पैसा न निकालें। मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो इसके अन्दर नियम भंग हुए हैं इनकी लाइसेंस देने में···

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आपस में बात कर रहे हैं। इस वक्त काम हो रहा है गम्भीर जनहित का। अगर आपको बात करनी हो तो बाहर जाकर करें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, यह हमेशा का कायदा है जब काल अटेंशन होता है तो सत्ता पक्ष के लोग हमेशा बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने पड़ोस में भी देखिए, दो नेतागण बैठे हैं; और सामने जो बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, सबको कह रहा हूं। जनता के हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उसकी बात हो रही है और आप लोग सब बातें कर रहे हैं।

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : This is the type of thing they do in the West Bengal Assembly also.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : They are incorrigible.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : They do it in the West Bengal Assembly also. They don't hear. This is the type of leaders they have.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। Please try to help me.

श्री मनीराम बागड़ी : जो लैटर आफ इन्टैंट मौपेड के लिए इश्यू किया गया था, उसके आधार पर इन्होंने बुकिंग 1982 से शुरू की है। लैटर आफ इंटैंट को कन्वर्ट करने के लिए 3 शर्ते हैं। इन्होंने तीनों में से सिर्फ एक शर्त पूरी की थी, 2 शर्ते पूरी ही नहीं कीं।

पहली शर्त कालोब्रेशन की थी इटली से। पता नहीं 3,4,5 साल से कब से इनकी कालाब्रेशन के लिए इटली से ममता चल रही है, यह तो इन्होंने लिख दी थी।

दूसरे फेस होना चाहिए था मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन उनका प्रोग्राम ही एप्रूव नहीं हुआ था और बुकिंग उससे पहले होती है।

सी० जी० क्लीयरेंस नहीं हुई थी लेकिन इन्होंने बाद में गवर्नमेंट को लिखा। यह भी क्लीयर नहीं किया गया था कि कितने पार्ट उसमें लगेंगे और उसके कितने परसैंट पार्टस विदेशों से मंगाए जायेंगे, बल्कि पहले साल में कितने लगेंगे और बाद में कितने लगेंगे? इन्होंने गवर्नमेंट को सिर्फ यह लिखा है कि 40 परसैंट तो ओ० जी० एल० से मंगा लेंगे और बाकी हिन्दुस्तान में ही मिल सकेंगे।

इसके बाद बुकिंग की एडवरटाइजमेंट उन्होंने की और मैंने बताया कि तीन किस्म से की। मंत्री जी के बयान के मुताबिक 105 करोड़ की बात है लेकिन अखबारों में जो आया है और लोगों से मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह राशि 200 करोड़ तक है। आजकल देश में विदेशी पूंजी और स्वदेशी पूंजी का भी बड़ा झगड़ा चल रहा है और बैक-डोर से इसको, मिस्टर** वह भी इसके शेयरहोल्डर हैं,

MR. SPEAKER : No names should be mentioned.

श्री मनीराम बागड़ी : विदेशी पूंजी जो लन्दन या दूसरे मुल्कों की है वह भी भारतीय पूंजी को खाने की कोशिश कर रही है।

(**व्यवधान**)

**Not-recorded.

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इतने नियमों का उल्लंघन करके एक ऐसे आदमी को, जिसके पास एसेट्स भी नहीं, मशीन भी नहीं, कोई साधन भी नहीं, आप इजाजत दे देते हैं कि वह बगैर साधन, बगैर मशीन, बगैर सब कुछ हुए इस तरह से लोगों से पैसा इकट्ठा कर लें ? मंत्री जी ने सिर्फ कंपनी के आधार पर बयान दिये हैं कि उनकी सूची के मुताबिक जो उनको जानकारी दी है।

क्या मंत्री जी ने अपने साधनों से सरकारी तौर पर कोई जानकारी करने की कोशिश की है ? क्या मंत्री जी इन पर 420 का धोखाधड़ी का मुकदमा चलायेंगे ? अगर नहीं चलायेंगे तो क्या आगे के लिए खुली छूट दे रहे हैं कि जनता का करोड़ों रुपया इस तरीके से मनमाने ढंग से लोग लूटते रहें और इस देश में गरीबों की लूट होती रहे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी, इनको कितने अर्से बाद इजाजत होती है, इनके पास कोई सामान नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, कोई कारखाना नहीं, फिर भी लाइसेंस मिल जाये तो ये लोग डिपाजिट कब इन्वाइट कर सकते हैं ? कोई ऐसा नियम है क्या ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : कंपनी डिपाजिट रूल्स हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसके पास सामान तो होना चाहिए, कोई बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, उसके बाद कोई ढांचा हो तभी इन्वाइट कर सकते हैं डिपाजिट या पहले ही इन्वाइट कर लेते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसके सम्बन्ध में जो अब तक प्रणाली रही है, वह कंपनी डिपाजिट रूल्स के माध्यम से संकलन होता रहा है। जैसा मैंने निवेदन किया है, हमने एक समिति बिठाई है इसी प्रश्न पर जब सदन में बात आई थी कि इसमें और कौन से प्रश्न उठते हैं विचार करने के लिए। सभी विभागों के सचिव या जो मुख्य अधिकारी हैं, उनकी समिति बनाई है जो इन्हीं प्रश्नों पर हमें राय दे।

उस दिन भी आपकी कृपा थी, जब मैंने उसका ऐलान यहीं पर किया था और मैंने इसका उल्लेख माननीय सदस्य के उत्तर में भी दिया है।

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER : You know, Professor, that you cannot speak like this.

(*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : लोहिया मशीन्ज और मारुति में बड़ा फ़र्क है।

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER : You talk about Lohia Machines now.

(*Interruptions*).

MR. SPEAKER : Nobody is allowed to interrupt like this. Mr. Minister, I would like you to reply to Mr. Bagri.

(*Interruptions*)**

MR. SPEAKER : No. They have said without my permission. We are talking of the present and of the future also.

Shri H.N. BAHUGUNA (Garhwal) : On a point of order. You, Sir, made a query. We were otherwise not involved in this. The query which you referred to the hon. Minister became a query of the House because you represent the House. The query you made was, what are the rules when you give this type of licence, this type of permission...

** Not recorded.

MR. SPEAKER : For my information I wanted to know.

SHRI H.N. BAHUGUNA : You represent the House and, therefore, I get involved. Therefore, you cannot tell me that I am not in order. What I am asking is...

MR. SPEAKER : No. Only Members whose names are in the list are allowed. You can be allowed on a separate thing. I can allow a debate on this.

SHRI H.N. BAHUGUNA : When you raise a question, we also get involved....

MR. SPEAKER : No. I have to conduct the business. I have to know certain facts, and I want to know.

SHRI H.N. BAHUGUNA : I am happy. To that extent the House gets involved and benefited.

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान्, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा था कि सम्मानित बागड़ी जी जैसे वरिष्ठ सदस्य जब कोई विषय इस सदन में उठाते हैं, तो हम आदर के साथ चेष्टा करते हैं कि हम इनके बयानों और सुझावों पर विचार करें। इस दृष्टिकोण से मैंने उनके द्वारा उठाए गए इस प्रश्न का बहुत ध्यान से अध्ययन करने की कोशिश की है।

सर्वप्रथम उन्होंने डा० लोहिया के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि प्रकट की है। मैं उससे सहमत हूं और मैं भी डा० लोहिया की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस सम्बन्ध में उनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं था, लेकिन चूंकि "लोहिया" नाम आ गया, इसलिए उनका उल्लेख करना आवश्यक हो गया।

यह सर्वमान्य है—और सम्मानित सदस्य भी इसे स्वीकार करेंगे—कि देश में इस समय साइकलों, मोटर साइकलों, स्कूटरों और मोपेड्ज सब की मांग बड़ी तेजी से बढ़ रही है। सम्मानित सदस्य ने साइकिलों के बारे में कहा। साइकिलों की खपत भी सारे देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। माननीय सदस्य को जानकारी है कि साइकल-युग में भारत पहले ही प्रवेश कर चुका था। अब वह दुपहियों के युग में भी प्रवेश कर रहा है। लोहिया मशीन्ज द्वारा केवल विज्ञापन निकालने से इतनी बड़ी संख्या में अर्जियां आना और उनके साथ पांच पांच सौ रुपए जमा होना इस बात का द्योतक है कि आज हमारे देश में अच्छे स्कूटरों की मांग कितनी बढ़ गई है।

प्लानिंग कमीशन के एक वर्किंग ग्रुप ने इस सम्बन्ध में एक स्टडी की है। उसके द्वारा अनुमानित किया गया है कि 1989-90 तक हमारे देश में 20 लाख टू-व्हीलर्ज, जिनमें मोटर, साइकल, मोपेड और स्कूटर शामिल हैं, की आवश्यकता होगी। इससे स्पष्ट होता है कि टू-व्हीलर्ज की मांग हमारे देश में बढ़ती जाएगी। 1982-83 में हमारे देश में 6.58 लाख टू-व्हीलर्ज की मांग है, जिसमें 2.83 लाख स्कूटर शामिल हैं। 1989-90 तक स्कूटरों की मांग 8 लाख तक हो जाएगी। केवल लोहिया स्कूटर ही नहीं, बजाज स्कूटरों और मोटरों साइकिलों की मांग 11 लाख लिखी हुई है।

जहां तक सैन्टो पब्लिक सैक्टर का सवाल है, उसके पास भी एडवांस आर्डर बहुत बुक हुए हैं। बजाज के पास दस-ग्यारह साल तक की वेटिंग लिस्ट मौजूद है। तब हमने यह नीति बनाई कि हम इनको लाइसेंस दें, ताकि लोगों की मांग पूरी हो सके। फिर हमने अच्छे मोटर साइकिल, मोपेड्स, स्कूटर आदि बनाने के लिए ही लाइसेंस दिए।

			In collaboration with
Enfield India Ltd. Madras	Motor Cycle	30,000	Zundap of West Germany.
Kelvinator of India Ltd., Faridabad	Mopeds/Scooters	1 Lakh	Garrelli of Italy.
Lohia Machines Ltd, Kanpur	Two wheelers/ Scooters	1 Lakh	Piaggia of Italy.
M. Krishnan, Madras	Motor Cycles/ Mopeds	2 Lakhs	Suzuki Motor Co. Japan.
Escorts Ltd. (under consideration)	Motor Cycles	1½ ,,	Yamaha of Japan.
Majestic Auto Ltd. Ludhiana (under consideration approval awaited)	Motor Cycles/ Mopeds	2 ,,	Handa of Japan.
Kinetic Engineering Ltd. (under consideration)	Motor Cycles/ scooters/mopeds/ 3 wheelers (including existing capacity)	2½ ,,	Handa of Japan.
AP Scooters	Light scooters 80 cc engine	60,000	Piaggio of Italy.

यह वेटिंग लिस्ट इतनी लम्बी हो रही है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूटर मिलेगा, इसको समाप्त करने के लिए, कम्पीटीशन लाने के लिए, अच्छा इंजन मार्केट में लाने के लिए, यह नीति हमने अपनाई। उसी के हिसाब से लैटर-आफ इन्टेंट दिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी कंपनी या किसी व्यवस्था के बारे में कोई राय देना, जब तक सारे तथ्य सामने न आ जायें, मैं अपनी ओर से उचित नहीं समझता हूं। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह कतई इरादा नहीं है कि अगर कोई गलती करता है या धोखाधड़ी करता है, तो उसको छिपायें। जैसा कि माननीय सदस्य ने सदन में घोषित किया था कि इस संबंध में एक कमेटी बनाई है, जो यह देखेगी कि जो डिपाजिट्स लिए जाते हैं, उनके क्या नियम हों। अब तक उसके कोई नियम नहीं थे। जो अब तक नियम थे, वे कंपनी डिपाजिट्स रूल्स के आधार पर थे। मेरे पास यह कम्पनी डिपाजिट्स रूल्स हैं। धारा-642 के अन्तर्गत जिसमें डिपाजिट्स लिए जाते हैं। लोहिया मशीन्स का यह पहला उदाहरण नहीं है, यह पिछले वर्षों से लगातार ऐसा होता आ रहा है। पब्लिक सैक्टर कम्पनीज ने भी इस तरह के डिपाजिट्स लिए हैं। बजाज भी लेता रहा है, टेलको ने भी लिए हैं। फियट-प्रिमीयर ने भी लिए हैं। जैसा कि आपने कहा मारुति भी ले रही है। पब्लिक सैक्टर हो या प्राइवेट सैक्टर हो, रिसोर्सेज मोबीलाइजेशन के लिए यह पद्धति अपनाई जाती रही है। इसका संबंध सीधा इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री से नहीं है, कम्पनी एफेयर्स विभाग इसको देखता है। रुपया इकट्ठा करने की यह कामर्शियल प्रैक्टिस है, यह माननीय सदस्य जानते हैं।

प्रश्न यह है कि क्या लोहिया मशीन्स कोई नया कारखाना है—ऐसी बात नहीं है। जो मेरे पास जानकारी है, उसके आधार पर सन् 1973

में यह कम्पनी कानपुर में स्थापित हुई। इस कंपनी की रिपोर्ट और ब्लैंसशीट मेरे पास है, उसके मुताबिक यह स्पष्ट होता है कि यह टैक्सटाइल मशीनरी बनाने का काम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। लोहिया मशीन, कानपुर, को 5 जुलाई, 1974 को क्रिम्पिग मशीन 50 नं० और टिविस्टिंग मशीन 72 नं० बनाने का लाइसेंस दिया। फ्रांस के कोलाबोरेशन से पंकी इन्डस्ट्री, कानपुर में क्रिम्पिग और एसेम्बली टिविस्टिंग मशीन बनाई। अप्रैल, 1977 से इस कंपनी को टैक्सचराइंजिग और टिविस्टिंग मशीन बनाने के लिए भी इजाजत दी गई। जो अधिकार इनको 1977 में दिया गया था, उसे फिर 6 फरवरी, 1981 को 250 मीटर पर-मिनट स्पेशल मॉडल बनाने का अधिकार दिया गया। इसका अर्थ यह है कि लोहिया मशीन कोई नया कारखाना नहीं है। यह सन् 1974 से कारखाना चल रहा है। टैक्सटाइल मशीन बना रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक सब मौजूद है, इसको देखा जा सकता है। अब इन्होंने इस नीति के तहत मोपैड स्कूटर आदि बनाने के लिए अर्जी दी है।

इन्होंने "पियाजा" नाम की कम्पनी के साथ फारेन-कोलाबोरेशन किया। सरकार ने इस नीति के तहत कि "टू-व्हीलर्स" की मांग बहुत ज्यादा है इनको इजाजत दी थी। श्रीमान्, मेरे पास इतनी संतुतिया आती हैं कि हमको स्कूटर दिलवाओ जिस का कोई हिसाब नहीं है। हमारे सम्मानित सदस्यों के पास भी बहुत से लोग जाते हैं कि हम को स्कूटर दिलवाओ, बाजार में 9-9 साल से स्कूटर नहीं मिल रहा है। लोक सभा के गेट पर जो पहरेदार साथी हैं, वे रोकते हैं कि 9 साल से स्कूटर नहीं मिला। पहली बार जब मंत्री बना तो मुझ से कहा गया कि स्कूटर दिलवाइये। स्कूटर की इतनी ज्यादा मांग को देखते हुए तथा यह सोच कर कि इस में इन्वेस्टमेन्ट बढ़े, इस का माडर्नाइजेषन हो, इस की एक्सपोर्ट की गुंजाइश को देखते हुए-बजाज ने एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा नाम कमाया है—हम ने निश्चय किया कि इस बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करें।

अब जहां तक प्रश्न है—इस कम्पनी ने शर्तों को पूरा किया या नहीं किया? जो सूचना मेरे पास है उसके मुताबिक इनके लैटर आफ-इन्टेन्ट में जो शर्तें लगाई गई थीं—

> "Arrangements for import of machinery will be finalised to the satisfaction of the Government."

यह इजाजत इनको 2 जून, 1982 को दी गई थी। हमारी जो कैपिटल-गुड्स की कमेटी है, जिसमें सारे विभागों के अधिकारी हैं, उन्होंने जांच करके हमारे पास रिकमैण्ड किया। उसके बाद उनको इजाजत दी गई कि वे कैपिटल गुड्स के लिए इम्पोर्ट करें और जो सूचना हमें दी गई है—उसके आधार पर उन्होंने 5 करोड़ 72 लाख रुपये की इण्डीजीनस मशीनरी के आर्डर, जो भारत में बनेगी, दिए है और 5 करोड़ 30 लाख रुपये के इम्पोर्टेड-इक्विपमेंट के आर्डर भी दे चुके हैं। बिल्डिग का काम इस समय चल रहा है, 50 हजार स्क्वेअर-फीट में पेन्टिग और असेम्बली शाप की बिल्डिग का काम जुलाई, 1983 तक हो जाएगा। इसी तरह से 50 हजार स्केअर-फीट में प्रेस शाप की बिल्डिग का काम भी हो रहा है, जिसके लिए वे पंकी इण्स्ट्रीयल शाप में एडीशन कर रहे हैं। इस तरह से उन्होंने शर्तों को पूरा करने का प्रयास किया है।

फारन-कोलाबोरेशन के अलावा जो दूसरी शर्तें थीं, जैसे—

> "Adequate steps shall be taken for anti-pollution measures."

उसके लिए भी इन्होंने आश्वस्त किया है कि हम एन्टी-पाल्यूशन के इक्विपमेंट भी लगायेंगे।

जो सूचना मेरे पास है उनसे ऐसा लगता है कि लैटर-आफ-इन्टैन्ट की जो शर्ते थीं, उन्हें मुख्यतया इन्होंने पूरा करने की चेष्टा की है। लेकिन जो जानकारी माननीय सदस्य ने दी है उस का भी हम पता लगवायेंगे और देखेंगे। हमारा

ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा कि किसी भी किस्म के गलत काम या धोखाधड़ी को प्रश्रय दें। इनके जो विज्ञापन अखबारों में छपे, उनसे इतने ज्यादा आवेदन-पत्र आ जायेंगे, इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। यही आशा थी कि जैसे नार्मल कोर्स में होता है उसी तरह से होगा, लेकिन जिस तरह से लम्बी क्यू लगी ऐसी कल्पना नहीं थी। अब जो कमेटी बनाई गई है उसमें कम्पनी-अफेअर्स के लोग हैं, इकानामिक अफेअर्स और हैवी इन्डस्ट्रीज के लोग हैं, इण्डस्ट्रीयल डवैलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट के लोग हैं तथा जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं वे लोग हैं, जो इस पर विचार करेंगे और इसमें अगर कोई धोखाधड़ी की बात आयेगी तो वे बतलायेंगे कि उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिये। वह कमेटी जो रिपोर्ट देगी वह सदन के सामने भी आयेगी और उस पर हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

इस सम्बन्ध में मैं फिर सम्मानित सदस्य, वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा इरादा औद्योगिक नीति को संतुलित आधार पर चलाने का है जिसका बागड़ी जी भी समर्थन करते हैं कि बड़े उद्योग, मझोले उद्योग, छोटे उद्योग, सबका सन्तुलित विकास हो, उसी सन्दर्भ में हमने ये लाइसेंस दिये हैं और एक लाइसेंस ही नहीं कई लाइसेंस दिये हैं और वे सब अपने-अपने कार्य कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में सम्मानित वरिष्ठ सदस्य और जो सुझाव देना चाहेंगे उन पर भी हम आदर-पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : उसकी कीमत का क्या होगी, यह आपने नहीं बतलाया ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : कीमत की सूचना मैं आपको बाद में दे दूंगा। कीमत के बारे में सूचना मेरे पास नहीं आई है, क्योंकि उसमें सेल्ज-टैक्स, एक्साइज डयूटी कितनी होगी, कम्पोनेन्ट्स पर क्या टैक्स होगा—इनकी अन्तिम रूपरेखा अभी नहीं बनी है, इसलिए कीमत निर्धारित नहीं कर पाये हैं, बाद में सदन की मेज पर रख सकता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : जो सवाल माननीय मंत्री जी से पूछा गया था, जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। सरकार के जो सारे प्रोविजन्स हैं या कानून हैं, उनके अनुसार भी जवाब देने की कोशिश नहीं की गई है और जिस बारे में आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया गया है। यह सरकार जिस ढंग से हिन्दुस्तान में कैपीटलइज्म, पूंजीवाद को मजबूत करने का काम कर रही है, वह अपनी जगह पर है लेकिन पिछले कई इस तरह के स्केन्डेल हुए हैं जो कि इस सरकार की नजरों में हैं और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार की और सरकार के मिनिस्टरों की मर्जी के बगैर, इजाजत के बगैर ये नहीं हो पाते और मेरा सरकार पर चार्ज है कि लोहिया मशीन्स को जिस वक्त इन्होंने लाइसेंस दिया था, उसके क्या रिपरकशन्स होंगे, ये अच्छी तरह जानते थे। पहले मारुति लि० का स्केन्डेल देश के लोगों के सामने आया जब उसको लाइसेंस दिया गया था। स्वर्गीय संजय गांधी का मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दोबारा आप इसको रिपीट करना चाह रहे हैं। जब वह कम्पनी नहीं चली, तो शेयरहोल्डर्स की मनी का क्या हुआ ? सरकार को इस देश के लोगों को बैंकों से करोड़ों रुपया देकर उसका अर्जन करना पड़ा। अब फिर लोहिया मशीन्स को लाइसेंस दे दिया गया है जबकि उसके पास न जमीन है, न मशीन है और न ही बिल्डिंग है। आपके साथ बैठ कर उन्होंने कोई बातचीत नहीं की और 110 करोड़ रुपये इस देश के लोगों से उन्होंने वसूल कर लिए। अब मंत्री जी ने यह कह दिया कि मुझे तो यह अन्दाजा नहीं था कि इतनी डिमान्ड होगी। मेरा कहना यह है कि इतनी डिमान्ड होगी, यह सरकार को पहले से मालूम था और यह सरकार लाइसेंस देकर कैपीटलइज्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। यह एक कामनसेन्स की बात है कि आज के जमाने में इस देश के लोगों की इतने स्कूटरों की

डिमान्ड होगी। यह एक कामनसेन्स की बात है और मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार कैपीटलइज्म को इस देश में न बढ़ाए।

आज आप हिन्दुस्तान में 18 मिलियन मीट्रीक टन तेल भी पैदा नहीं कर पाते और लाइसेन्स पर लाइसेन्स स्कूटर बनाने के दिये जा रहे है। चीन जो एक इन्डिपेन्डेंट कन्ट्री है और हर स्फेयर में अपने पैरों पर खड़ा है, वहां पर 40 लाख साइकिलें चलती हैं। वह 100 मिलियन मीट्रिक टन तेल पैदा करता है। वह स्कूटरों के लिए लाइसेन्स नहीं देता और मैं तो यह कहता हूं कि यह जो लाइसेन्स देने की पालिसी है, यही गलत है। आज इस देश में कम से कम 37 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनके लिए रोटी, कपड़े और मकान का कोई इन्तजाम नहीं है और यहां पर आप स्कूटर और टी० वी० का स्वाद पैदा कर रहे हैं और इस काम के लिए पियागो कम्पनी से, जो इटली की कम्पनी है, उसके साथ कोलावरेशन कर रहे हैं क्या वह एक कैपीटेलिस्ट मुल्क नहीं है। आप उन मुल्कों के द्वारा और यहां के पूंजीपतियों के द्वारा इस गरीब मुल्क के लोगों को चूसने का काम करवा रहे हैं और लोगों की मेहनत से कमाई हुई पूंजी को ये पूंजीपति चूसने का काम कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आपकी जो यह बुनियादी पालिसी है, उस पर आप प्रतिबन्ध लगाएं और इस तरह के लाइसेन्स न दें। लोहिया मशीन्स ने 110 करोड़ रुपये लोगों से इकट्ठा किया है। कहा यह जा रहा है कि 150 हेक्टेयर जमीन उन्होंने ले ली है लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी भी लोहिया मशीन्स ने कोई जमीन नहीं ली है। उस रोज भी माननीय सदस्यों ने कहा था कि इतनी ज्यादा बुकिंग इस स्कूटर की हुई है कि 60 साल में भी लोगों का नम्बर नहीं आएगा। अगर आज मैं अपने नाम से स्कूटर बुक कराऊं तो अगले 60 साल में पता नहीं कि मैं इस संसार में रहूं या न रहूं। लोहिया मशीन्स एक साल में 1 लाख स्कूटर देने की क्षमता रखती है, यह बताया गया था लेकिन मेरा कहना यह है कि वह 1 लाख स्कूटर एक साल में पैदा नहीं कर सकती लेकिन अगर वह इतने स्कूटर एक साल में बना भी लेती है, तो भी 50-60 लाख लोगों ने स्कूटरों की बुकिंग कराई है और इस हिसाब से 60 साल के बाद ही कुछ लोगों का नम्बर आएगा।

अध्यक्ष जी ने इसमें बहुत इन्ट्रेस्ट लिया है और माननीय तिवारी जी को पता होगा कि उस दिन स्पीकर साहब ने यह कहा था कि इन लोगों को अपना स्वर्ग का पता भी दे देना चाहिए, ताकि स्कूटर वहां भेजे जा सकें और एक बहुत सही बात उन्होंने कही थी। आप दुनिया की सबसे बड़ी जम्हूरियत की सरकार में बैठे हैं और 60-70-80 लाख स्कूटरों की बुकिंग हुई है।

आप देखिये कि लोगों को किस तरह से चीट किया गया। कहा गया कि वैसे तो फार्म 5 रुपए का है, लेकिन कोई थोक में लेना चाहे तो तीन रुपए का हैं। इस तरह से 3 और 5 रुपए में फार्म बेचकर करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया गया। इतना ही नहीं पूरे देश में 4-4 लाख रुपए लेकर एजेंट बनाए गए हैं। आज कानपुर के छोटे से दफ्तर में लोग 4-4 लाख रुपया लेकर घूम रहे हैं। 110 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया है और सरकार कहती है कि हमको मालूम नहीं है। इससे बड़ा और क्या स्कैंडल हो सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या लोहिया मशीस के खिलाफ प्रासीक्यूट करने जा रहे हैं या नहीं। उनको लाइसेन्स देने के समय कोई कंडीशंस तय की गई थीं या नहीं। नेगोसिएशन के समय आपकी ब्यूरोक्रेसी ने कोई शर्तें तय कीं या नहीं? कोई शर्तें तय नहीं की गई। योजनाबद्ध तरीके से लाइसेंस दिया गया। यह तो उनका दुर्भाग्य है कि मामला हाउस में उठा और आपके ध्यान में आया।

स्कूटर की कीमत का पूरे देश में प्रचार किया गया। कहा गया कि पियागो कोलोबरेशन से कीमत ज्यादा होगी, लेकिन हम हिन्दुस्तान की सड़कों पर करीब 9000 में इसको लाएंगे।

The cost price itself of VESPA XE according to this breakup will not be less than Rs. 10,000/- and the cost of 150 CC Bajaj scooter on road is Rs. 8457.50.

उद्योग मंत्री कहते हैं कि हमको पता नहीं है। आपने लाइसेंस दिया है और आपको मालूम नहीं है कि इसकी कीमत क्या होगी ?

दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा स्कूटर हिन्दुस्तान में है। आज वैस्पा 16 हजार में बिक रहा है। यह स्कूटर भी जब मार्केट में आएगा तो 16 हजार में ही बिकेगा।

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि 1983 नवंबर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। जहां बिल्डिंग नहीं है, 40 प्रतिशत मशीनें आयात करनी हैं वहां पर 1983 में प्रोडक्शन कैसे शुरू हो सकता है। अभी कुछ भी आयात नहीं किया गया है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप लोहिया मशींस के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे या नहीं। जिन लोगों को एजेंट बनाकर रुपया लिया गया है, उनका पैसा वापिस कराएंगे या नहीं ? आज राजस्थान कैनाल को 247 करोड़ रुपये की जरूरत है। वहां पर आपने 17 करोड़ रुपया दिया है। क्या इस 110 करोड़ रुपये को इनसे लेकर राजस्थान कैनाल के काम में नहीं लगाया जा सकता ? यह मुल्क के लोगों का पैसा है।

एक बात और बताना चाहता हूं। बजाज और लोहिया मशीन्स के आपस में रिलेशन हैं। उनका षड्यंत्र है। वे इसको चलाना नहीं चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय लाइसेंस दिया गया था उस समय इनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या थी। 110 करोड़ रुपया इकट्ठा करने से पहले उनकी कैपिटल कैपेसिटी क्या थी ?

इन सब चीजों का जवाब मैं जानना चाहता हूं। लेकिन जिस ढंग से वरिष्ठ सदस्य बागड़ी जी को जवाब दिया गया है, उस ढंग से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ का जवाब कनिष्ठ का कैसे हो सकता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य ने बड़ी प्रभावपूर्ण भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पूंजीवाद, समाजवाद और अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवाद की बात उन्होंने की है। मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि यह एक लम्बा विवाद है। जो सूचना मुझे मिली है, उस आधार पर लोहिया मशीनज़ ने 18 करोड़ 20 लाख रुपये पब्लिक सेक्टर कम्पनीज़ में डिपाज़िट किए हैं। बाकी जो दूसरी कंपनियां हैं उनमें 53 करोड़ 50 लाख रुपये डिपाज़िट किए हैं।

*(Interruptions).***

ये 9 परसेंट देंगे, पांच-सौ रुपये पर। मेरे पास बहुत लम्बी सूची है। आप चाहें तो मैं पढ़ सकता हूं।

*(Interruptions).***

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ 6 परसेंट का फर्क है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जो सूचना मांगी गई है, वही मैं दे रहा हूं। हमने इस सदन में एक कमेटी की घोषणा की थी...(**व्यवधान**)

श्री मनी राम बागड़ी : यह जो समिति आपने बनायी है, यह कितने दिनों में रिपोर्ट दे देगी ?

श्री जगपाल सिंह : हैवी इंडस्ट्रीज की जो कमेटी बनी है, वह कब तक रिपोर्ट देगी ?

*(Interruptions)***

**Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : कुछ-न-कुछ टाइम बाउण्ड तो किया ही होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : तीन महीने में रिपोर्ट दे देगी।...

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नॉट अलाउड।

(*Interruptions*).

श्री नारायण दत्त तिवारी : जब तक कोई बात साबित न हो जाए तब तक प्रासीक्यूशन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। एस्टेबलिश कार्मशियल प्रैक्टिस के आधार पर जमा हुए हैं। अभी यह स्टेज नहीं आयी है कि इसमें प्रासीक्यूशन हो सके। जैसे ही हमको कुछ बात धोखाधड़ी के बारे में मालूम होगी ...(व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप भी संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, हम भी चुप बैठ जाते हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : खुद, तिवारी जी भी संतुष्ट नहीं हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : वे तो संतुष्ट हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि मारुति का मामला एडजार्नमेंट मोशन के रूप में आपके सामने रखा तो आपने उसी वक्त कह दिया कि ऐसे कुछ और गंभीर मामले हैं। हम इस पर कालिंग अटेंशन ले रहे हैं। वस्तुतः आपने यह एक बहुत पवित्र काम किया है क्योंकि यह कालिंग अटेंशन स्वीकार कर लिया है।

(*Interruptions*).

गंगा स्नान तो हमारे यहां चलकर कर लेंगे। लेकिन तिवारी जी भी वैसा ही पवित्र काम कर लें तब।

मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अभी श्री नारायण दत्त तिवारी जी बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग संभाले हुए हैं। इस विभाग पर सरकार को बहुत बड़ा नाज़ है। लेकिन 35 वर्ष की आजादी के बाद आज आपको मालूम हो रहा है—इस कांड से कि, देश में अब आप यह महसूस कर रहे हैं कि स्कूटरों की भारी आवश्यकता है। अभी आपने ही इसको स्वीकार किया है। अब आप स्वयं कह रहे हैं कि बजाज, टेलको, मारुति तथा अन्य और कई कम्पनियां हैं जो इसी प्रकार की प्रैक्टिस अपना रही हैं। मेरा भी ध्यान उधर है। आप सबूत मांग रहे हैं समझ में नहीं आता है कि आपको इससे बड़े और किस सबूत की जरूरत क्या है? जगपाल सिंह जी ने जो कहा कि मुकदमा चलाया जाए, उसको चलाने में आपको क्यों परेशानी हो रही है? आपने अभी स्वयं कहा है कि बजाज, टेलको, मारुति आदि कम्पनियां भी इसी प्रकार की पद्धति अपना रही हैं, पैसा हड़प कर रही हैं। जब यह बात भारत सरकार के उद्योग मंत्री जी को मालूम है तो फिर कोई कार्रवाई करने से वह हिचक क्यों रहे हैं? और कौन सा सबूत आपको चाहिये?

बजाज स्कूटर की बात से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। इसकी भी यही स्थिति है। आज से नहीं पंद्रह साल से बजाज स्कूटर की भी ऐसी स्थिति बना दी गई है। उसमें सरकार का हाथ है। आदमी सोना खरीदना नहीं चाहता, जमीन खरीदना नहीं चाहता लेकिन पांच सौ रुपया जमा करके बजाज स्कूटर खरीदना चाहता है? आखिर क्यों? इस

**Not recorded.

वास्ते कि जिस दिन उसको बजाज स्कूटर मिलेगा उसी दिन आठ हजार रुपया ब्लैक मनी उसके हाथ में आ जाएगी। यह स्थिति सरकार की बनाई हुई है।

इतना ही नहीं। हमारे मित्र ने अभी जिक्र किया है। मैं गहराई में जाना नहीं चाहता हूं। मेरे पास यह पत्रिका है। यह ताजी खबर प्रस्तुत कर रही है। यह मारुति लिमिटेड के बारे में है। इसमें कहा गया है, जनता के साथ पांच सौ करोड़ का धोखा। आ गया भारत सरकार का नया करिश्मा। विदेश में बनी देशी जनता कार जहाँ सुजुकि लिखा है वहां मारुति पढ़ें। भारत सरकार के आदेश से। इस पत्रिका का नाम भू भारती है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस विषय पर ही रहें। पब्लिक अण्डरटेकिंग्स कमेटी है वह इसको देख सकती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं अपने विषय से ही सम्बन्धित बात कर रहा हूं। बाहर जाकर बात नहीं करूंगा। यह भी एक लूट का तरीका है जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। मारुति के जो विशेषज्ञ हैं वे भी बाहर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये 1983 में कार दे देंगे। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं। मारुति, लौहिया, बजाज आदि में कोई डिफ्रेंस मैं नहीं समझता हूं। मेरे पास सारी की सारी सूचना मौजूद है। इस पत्रिका में जो छपा है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। लौहिया मशीन उद्योग के बारे में इटली की एक कम्पनी जो वैस्पा बनाती थी जब एक कम्पनी से अपना समझौता भंग किया तो उसने हिन्दुस्तान के दो कारखानों से समझौता किया और उस समझौते का अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तो उसमें भी धोखे की बू आपको आएगी। इटली की पियागिओ कम्पनी से लौहिया मशींज ने 150 सी. सी. क्षमता वाले एक लाख स्कूटर बनाने का समझौता किया। इस कम्पनी द्वारा जो डिबेंचर पत्र जारी किए गए उसके पीछे भी एक इतिहास है जिसको मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आप कहते हैं कि हम को जानकारी नहीं है। दो सौ रुपये फी डिबैंचर के हिसाब से जारी किए गए। इनके साथ आकर्षण यह जोड़ा गया कि जिसको ये ऋणपत्र मिल जाएंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर वैस्पा एक्स-ई स्कूटर पहले दिया जाएगा।

13.00 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*).

लोग गुमराह हो गए। एक तो विदेशी कंपनी का साझा दूसरे सरकार की चुप्पी। लोगों में होड़ लग गई, स्टाक ऐक्सचेंज में फार्म समाप्त हो गए। इस लौहिया मशीन के, 33 लाख ऐप्लीकेशन फौर्म्स बिके और एक फौर्म की कीमत 5 रु० थी। इसी से एक करोड़ 65 लाख रु० की आमदनी इसको हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह रुपया किस फंड में जाएगा? 2 लाख 25 हजार ऋणपत्र जारी करना था कम्पनी को, लेकिन 7,74,973 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इतने ही ऋणपत्र इस कम्पनी ने जारी किए। आपके हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख रु० आया है। लेकिन 1,97,598 लोगों ने केवल ऋणपत्र खरीदे हैं 500 रु० के हिसाब से तो केवल 200 करोड़ रु० का घपला इसमें ही नजर आता है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? अगर नहीं, तो जो मैंने जानकारी दी है उसके बाद आप क्या करने जा रहे हैं लौहिया स्कूटर के खिलाफ जो जानकारी मैंने दी है वह सही है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : How much time do you require to put questions?

SHRI RAJNATH SONKAR SHASTRI : Five-seven minutes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue after lunch. The House stands adjourned to meet at 2 P.M.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Contd.

Reported Collection of a large sum of money by Messers Lohia Machines Ltd., Kanpur as advance for booking of Vespa-XE Scooters—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Rajnath Sonkar Shastri. He has already given sufficient ground. He can now put the question. There are other important discussions coming up under rule 193 and one half-an-hour discussion.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैं पहले डिबेंचर्ज के सम्बन्ध में बता रहा था। लौहिया मशीन्ज ने दो तरीके से पैसा वसूल किया। पहले तो उन्होंने स्कूटर की बुकिंग के लिए पांच-पांच सौ रुपए जमा कराए और फिर उन्होंने डिबेंचर्ज अलग से जारी किए। अन्य मामलों में यह रुपया पोस्ट आफिस में जमा होता है। लेकिन सुनने में आया है कि लौहिया मशीन्ज ने सारे का सारा रुपया सीधे अपने नाम जमा करवाया। उन्होंने अपने लक्ष्य से साढ़े सोलह गुना ज्यादा पैसा इकट्ठा किया। इतना ही नहीं, डिबेंचर्ज में काफी धांधली हुई। उन्होंने वादा किया था कि 9 में से एक व्यक्ति को जरूर डिबेंचर देंगे। उन्होंने काफी लोगों को दिया भी, लेकिन बहुत से ऐसे केसिज सामने आए हैं, जिनमें से 15 में से एक व्यक्ति को भी डिबेंचर नहीं मिला। यह मामला काफी गम्भीर है। क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर गया है; यदि हां, तो डिबेंचर्ज के प्रदान में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनके बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

मैंने पहले कहा है कि पांच रुपए प्रति फार्म के हिसाब से 33 लाख फार्म बेचे गए। इस तरह एक करोड़ 65 लाख रुपया केवल फार्म्ज से उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि यह 165 लाख रुपया किस फंड में गया है, क्या यह प्रधान मंत्री के रिलीफ फंड में या किसी अन्य रिलीफ फंड में जाएगा, उसका क्या उपयोग होगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि लौहिया मशीन्ज ने किस आधार पर ऋणपत्र जारी करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है। क्या उनकी फैक्टरी लग गई है, क्या उत्पादन शुरू हो गया है, क्या स्कूटर की कीमत तय कर दी गई है ? क्या उन्होंने यह घोषणा की है कि यह रुपया कब तक जमा होगा ? कब तक बुक कराने वाले को स्कूटर की सप्लाई होगी ?

लाइसेंस के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार के कुछ नियम हैं कि बिना जमीन और बिना फैक्टरी के और बिना कीमत तय किए हुए लाइसेंस दिया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार रुपया इकट्ठा करने पर सरकार का कोई नियंत्रण है, अगर नहीं है, तो क्या सरकार नियमों में ऐसा एमेंडमेंट करेगी, जिससे उस पर सरकार का नियंत्रण हो और कम्पनियाँ कानून की कमी का फायदा उठाकर रुपया इकट्ठा न कर सकें।

मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें यह अन्दाज नहीं था कि इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन अब तो उन्हें अन्दाज हो गया है। 110 करोड़ रुपया इकट्ठा करने की बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। लेकिन हम लोगों का कहना है कि 400 करोड़ से ज्यादा रुपया इकट्ठा किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि लौहिया मशीन्ज ने धोखा देकर देश के लोगों से जो इतना रुपया इकट्ठा किया है, क्या मंत्री महोदय उसे यह रुपया वापस करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश देंगे। लौहिया मशीन्ज ने जो इतनी बड़ी धनराशि जमा करा ली है, सरकार इसको सुरक्षित रखने की क्या व्यवस्था करेगी ? उन्होंने आवेदन दिया है कि हमने सामान और मशीनें ले ली हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिशा में एक

प्रतिशत से ज्यादा कार्यवाही नहीं की है। क्या सरकार इस रुपये को सुरक्षित रखने के बारे में व्यवस्था करेगी?

मान्यवर, अन्तिम बात मैं यह पूछ रहा हूं—जैसाकि आपने अपने बयान में दिया है—जो कम्पनी के बयान पर आधारित है—जिससे सरकार का बयान भी सन्देहास्पद हो जाता है—

> "उसने औद्योगिक लाइसेंस व विदेशी सहयोग करार के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाये हैं।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि ये प्रभावी कदम अब क्यों उठाये गये हैं? क्या चार-पांच दिन पहले हाउस में इस संबंध में विवाद हुआ था उसकी वजह से उठाये गये? किस आधार पर प्रभावी कदम उठाये गये हैं? इसका मतलब है कि अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे तथा ये प्रभावी कदम क्या हैं? कंपनी ने बतलाया है कि सात माह के बाद यानी नवम्बर, 1983 में स्कूटर का निर्माण प्रारम्भ होने की संभावना है। आप देखिये—सात माह शेष हैं, बिल्डिंग बननी है, मशीनों के गाड़ने का निर्माण कार्य होना है। ऐसी स्थिति में क्या मंत्री जी को विश्वास है कि स्कूटर सात माह में रोड पर आ जाएगा—इसके बारे में भी मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाहूंगा।

अन्तिम बात यह कहना चाहूंगा—यह मामला बहुत गंभीर है। देश में मारुति लि०, लोहिया मशीन्ज, अन्य कई कंपनियों ने इसी प्रकार की बड़ी भारी ठगी की है और इस ठगी को किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। इस मामले पर केवल उत्तर दे देने से काम नहीं चलेगा। यदि इस पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई तो यह मामला कल, परसों या उसके बाद फिर उठेगा और सरकार को जवाब देना होगा। यहां पर करोड़ों रुपयों का गबन हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस भारी स्कैंडल से बचाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे है?

MR. DEPUTY-SPEAKER : You did not put one question, that is, how they have selected the name of the great man, Mr. Lohia for the name of the Company. You did not put that question.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हमारी इस चीज को दो भागों में बांट दिया गया, एक पहले हो गया, एक अब हुआ है।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am helping him. He did not put that question only.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Minister, if you know some answer to the last question, you can reply to that also.

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमान्, मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डा० लोहिया जी के शुभ नाम से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा मैंने प्रारम्भ में ही कहा था—लोहिया सरनेम है। इस के अध्यक्ष ख्याति-प्राप्त उद्योगपति श्री राम प्रसाद नेवतिया हैं। उनके नाम को सब जानते हैं, वे लोहिया मशीन्ज़ के चेयरमैन हैं और श्री लोहिया इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : हम तो नहीं जानते, तिवारी जी। वे शायद इतने प्रसिद्ध-विख्यात नहीं हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्री रामप्रसाद नेवतिया भूतपूर्व लोक सभा सदस्य रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : नेवतिया को तो जानते हैं, लेकिन उद्योगपति के रूप में नहीं जानते।

श्री नारायण दत्त तिवारी : वही नेवतिया

हैं जो पहले लोक सभा सदस्य थे। वही इसके चेयरमैन हैं।

(*Interruptions*).**

वही हैं।

(*Interruptions*)**

पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—मेरे जोशीले भाई शास्त्री जी, मैं उनको पहले जानता हूं—कहीं भी पिछड़े क्षेत्र में जब कभी लैटर-आफ-इन्टेन्ट (आशय-पत्र) दिया जाता है तो वहां पर यह नहीं होता है कि पहले कारखाना लगाया जाय।

आशय पत्र का अर्थ ही यह है कि आशय है कि हम लगायेंगे। जब कभी पहले कारखाना लगता है, तो लैटर आफ इन्टेंट का अर्थ यह नहीं है कि पहले कारखाना लगाया जाए, तब लाइसेंस दिया जाए या लैटर आफ इंटेंट दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। देश में आप जितने भी कारखाने देख रहे हैं, इनका प्रारंभ इसी प्रकार हुआ है कि लैटर आफ इन्टेंट दिया गया, कोला-बोरेशन हुआ और तब ये कारखाने लगे हैं। मैंने पहले ही बताया कि लोहिया मशीन का कारखाना वहाँ पहले से ही लगा है। अब यह नए क्षेत्र में कारखाना लग रहा है। इसके लिए 11 करोड़ रु० की मशीनरी का आर्डर दिया जा चुका है, जो मई-महीने में आनी शुरू हो जाएगी और सितम्बर, 1983 तक ये सारी मशीनें, बाहरी या भीतरी, आ जायेंगी। जैसा कि कहा गया है। दूसरी बात स्कूटर को बनाने के लिए 100 मैनेजर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है, जिसमें से 60 को नौकरी पर रखा जा चुका है और बाकी के लिए ट्रेनिंग, भर्ती वगैरह का प्रबन्ध किया जा रहा है।

जहां तक पैसे का सवाल है, जैसी कि अब सूचना मिली है 53.5 करोड़ रु० अच्छी मानी जाने वाली प्राइवेट सैक्टर कंपनीज में लगाया है, जिसकी लिस्ट मेरे पास है। 18 करोड़ 20 लाख रु० पब्लिक सेक्टर में लगाया है, 33 करोड़ 40 लाख रुपया बैंकों और फाइनेन्शियल इन्स्टीचूशन्स में जमा है, 6 करोड़ रुपया हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनांस कारपोरेशन, जो आई० डी० बी० आई० आई० सी० आई० सी० आई० की सब्सीडियरी है, उसमें जमा है।

(*Interruptions*)**

अलग-अलग है, इसकी बड़ी लम्बी लिस्ट है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इसको आप डिटेल में दे दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इसका अर्थ यह है कि रुपए को सावधानी से रखने का प्रयास किया गया है। यह बताया गया है कि डिपाजिटर्स का रुपया सुरक्षित हो और उनको ब्याज मिले। इसके अलावा यदि कोई चाहता है, तो वह स्कूटर कैंसिल कराकर पैसा रिफण्ड करा सकता है, सात परसैंट ब्याज पर। जैसे बजाज का होता है, ट्रक का होता है, टाटा का हो सकता है, फीयट कार का हो सकता है। इसी प्रकार जो लोहिया के पास पैसा जमा है, वह भी कैंसिल करके रुपया रिफण्ड कर सकते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि लोगों ने स्कूटर कैंसिल कराया हो और कितनी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जरूर कराया होगा, लेकिन ऐसी कोई सूचना इस समय नहीं है। अभी भी राय दी जा सकती है, इस की पूरी छूट है। इसमें मजबूरी नहीं है कि रुपया जमा हो गया तो वह रुपया रिफण्ड नहीं करा सकता है। जिसको विश्वास नहीं है, वह करा सकता है।

जहां तक बिल्डिंग का प्रश्न है, बिल्डिंग-1 50 हजार स्कैयर फिट, इस महीने तक पूरी हो

**Not recorded.

जाएगी। बिल्डिंग-2 जुलाई 1983 तक पूरी बन जाएगी। स्कूटर इस साल के आखिर में नवम्बर महीने तक मार्केट में लाने का आश्वासन दिया है। स्कूटर अवश्य मार्केट में आ जाएगा।

जहां तक फार्म्स का सवाल है, इसका विवरण भी हमने मंगाया है। 33 लाख फार्म्स बिके हैं। यह अन्दाजा लगाना मुश्किल था कि इतने फार्मों की मांग आएगी। इसका अन्दाजा विज्ञापन निकालने से पहले नहीं लगाया जा सकता है। यह कहना ज्यादती होगी कि पहले से मालूम हो जाता है। मुझे यह आश्चर्य हुआ कि इतनी ज्यादा स्कूटरों की मांग देश में है। मैं समझता हूं कि इसका अन्दाजा वर्किंग ग्रुप को भी नहीं था कि इतने स्कूटरों की मांग आ जाएगी। लेकिन इसका पूरा हिसाब हमारे पास है—कम्प्यूटराइजेशन प्रिंटिंग में 11 लाख 65 हजार रु० पैकिंग कास्ट एक लाख 59 हजार, ट्रांसपोर्टेशन 81 हजार, इंशोरेंस 25 हजार और अथॉराइज्ड रिप्रजैन्टेटिव को 65 लाख रुपए दिए गए।

स्टेट बैंक का जो खर्च हुआ कमीशन वगैरह में, वह 6 लाख 75 हजार रुपये हुआ, कम्प्यूटर प्रोसेसिंग में 33 लाख रुपये खर्च हुए और छपाई, माइक्रो फिल्मिंग, सोटिंग वाइंडिंग आदि में 31 लाख रुपये खर्च हुए हैं। यह पूरा हिसाब कम्पनी ने भेजा है। यह सारा मामला कम्पनी एफेयर्स का है और जितनी भी इस प्रकार की डिपोजिट की गड़बड़ होती है, उसको देखने का काम इंडस्ट्रीज विभाग का नहीं है बल्कि कम्पनी एफेयर्स विभाग का है और इसमें अगर कोई गड़बड़ होती है, तो वह जरूर देखेगी। जहां तक फार्म्स की सप्लाई की बात थी, वह मैंने बता दी है। मैं यह भी बता दूं कि इस सब को देखने के लिए एक कमेटी बनी हुई है।

Shri S.M. Ghosh, Secretary Department of Industrial Development —Chairman

Shri D.V. Kapur, Secretary Department of Heavy Industry —Member

Shri R.K. Kaul, Additional Secretary, Deptt of Banking —Member

Shri V.K. Dar, Development Commissioner, Small Scale Industries —Member

SHRI S.M. Dugar, Member, Company Law Board, Deptt of Company Affairs —Member

Shri M.C. Gupta, Joint Secretary, Department of Heavy Industry —Member-Secretary

यह जो कमेटी है, यह मिल भी चुकी है और तीन महीने के अन्दर यह अपनी रिपोर्ट दे देगी, इसकी मुझे पूरी आशा है।

डिबेन्चर्स के बारे में भी माननीय सदस्य ने पूछा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हर कम्पनी को डिबेन्चर्स फ्लोट करने का अधिकार है और साधनों को जुटाने के लिए ऋण-पत्र जारी करने का एक जाना माना तरीका है। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने सवाल पूछे थे, उनका जवाब नहीं आया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not permitting anybody except Shri B.D. Singh. Every time you cannot get up. You are a senior Member. They are all waiting.

(*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am telling you that five names have been given under the call-attention. Three hon. Members have already spoken. If you have already spoken, should I not call him ? Are you not doing injustice to him by interruptions ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मेरे प्रश्नों का

तो उत्तर मिलना चाहिए। कालिंग एटेंशन में मेरा नाम है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : If I am to conduct the proceedings of the House strictly according to the Rules, none of you would have got this chance. You must be kind to us as we are always kind to you.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जो सवाल पूछे हैं, उनका जवाब मिलना चाहिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is an Agenda today. Should we not complete it ? Yes, Shri B.D. Singh to speak.

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोहिया मशीन्स का जहां तक सम्बन्ध है, उसके बारे में बहुत सारी बातें जाहिर हो चुकी हैं। इस कंपनी के लोगों ने सरकारी अधिकारियों से मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और एक साजिश की है। मान्यवर, इस बारे में इंक्वायरी की बात मंत्री जी कर रहे हैं और यह बताया है कि हम ये कदम उठाने जा रहे हैं। इसके पहले सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और उसने कुछ नहीं किया।

सबसे पहले इस सम्मानित सदन में पिछली 2 मार्च को हमारे एक साथी सदस्य ने इसके बिषय में एक प्रश्न रखा था। माननीय बहुगुणा की पार्टी के श्री अशफाक हुसैन ने जब इस सवाल को एक स्टार्ड क्वेश्चन के रूप में रखा था, तब यहां पर बड़ा हंगामा हुआ था और पूरे सदन में इस बात से बहुत चिन्ता हुई थी और तब माननीय मंत्री जी ने इसके संबंध में अपने जवाब दिये थे। अब एक प्रश्न के उत्तर में, जो मैं समझ पाया हूं, माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि इस महीने तक उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी और 2 मार्च को जो मंत्री जी ने जवाब दिया था, उसमें उन्होंने यह बताया था कि केवल भूमि का क्रय किया गया है और अभी नींव नहीं पड़ी है। अब मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि बिल्डिग बनकर तैयार हो जाएगी और प्रोडक्शन शुरू करने के लिए मशीनों का आईडेंटीफिकेशन हो चुका है और कांट्रैक्ट दिया जा चुका है।

दो मार्च का आपका यह जबाब है। मेरे पूर्व-वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं 2-4 सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा।

आपने बताया है कि 21 लाख लोगों ने स्कूटर बुक कराया है और 105 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। फार्म 5 रुपये के, 21 लाख बेचे गए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : 33 लाख फार्म बिके हैं।

श्री बी० डी० सिंह : मेरे खयाल से यह पहली कंपनी है जिसने फार्म के पैसे चार्ज किए हैं। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ है। जिस समय लाइसेंस दिया गया उस समय यह जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि क्या टर्म्स एण्ड कंडीशंस होंगी ? क्या योजना है, कब तक तैयार हो जाएगा, क्या कास्ट होगी, इन सब चीजों की जानकारी नहीं ली गई। आपने इतना बता दिया कि प्राइस अभी तय नहीं है। इतनी बड़ी चीज होने जा रही है और पता नहीं है कि कीमत क्या होगी और प्रोडक्शन कब शुरू होगा। ये चीजें मंत्रालय द्वारा नहीं देखी गईं। इसका मतलब है कि बारीकी से देखे बगैर लाइसेंस दिया गया है।

आपने बताया है कि सीनियर आफिसर्स की कमेटी बना रहे हैं। इस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं ? किन-किन मुद्दों पर यह कमेटी जांच करेगी ? दूसरी शंका मुझे यह है कि जिन अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, उन अधिकारियों की साजिश तो इसमें है ही। वे तत्वों को कैसे प्रकाश में लाएंगे ? इस मामले की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए, ताकि तथ्यों का पता लग सके।

इस स्कूटर कंपनी में एक लाख स्कूटर प्रति वर्ष तैयार होंगे। 21 लाख स्कूटर बुक किए गए हैं। इस हिसाब से 20 साल में नंबर आएगा। इस तरह से इतनी बुकिंग करने की इजाजत सेके दी गई? इकनामिक टाइम्स में एक न्यूज है "लोहिया मशींस एक्सटेंशन मूव अंडर स्टडी।" क्या लोहिया मशींस की तरफ से इस तरह का कोई प्रपोजल सरकार के विचाराधीन है। उन्होंने एक लाख से बढ़ाकर 4 लाख प्रति वर्ष प्रोडक्शन करने का प्रप्रोजल रखा है? अगर इस तरह का प्रपोजल विचाराधीन है तो इसके क्या कारण हैं। अभी वहां एक लाख प्रतिवर्ष का प्रोडक्शन शुरू भी नहीं हुआ है तो चार लाख प्रतिवर्ष का प्रपोजल कैसे विचाराधीन है। (**व्यवधान**)

बताया गया है कि 9 प्रतिशत के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। जब कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है तो किस दर से ब्याज लिया जाता है? इन पर भी वही दर क्यों लागू नहीं होनी चाहिए?

जैसा अभी आपने बताया है कि एक लाख से चार लाख तक विस्तार के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है, तो क्या इसमें जो स्कूटर बनेंगे वे केवल घरेलू उपयोग के लिए होंगे या इसमें एक्सपोर्ट की व्यवस्था भी की जायेगी? आपने कहा है कि 21 लाख स्कूटर बुक हो गए हैं। मुझे व्यक्तिगत जानकारी है कि जो वास्तविक उपभोक्ता हैं उन्होंने इतने बुक नहीं किए हैं। ज्यादातर जो पैसे वाले हैं, उन्होंने अपने परिवार के भिन्न-भिन्न सदस्यों के नाम से बुक किए हैं। जब नम्बर आता है तो ब्लैक में बेच देते हैं। इसी प्रकार जिन कंपनीज के स्कूटर्स की स्केरसिटी है, उनका भी ब्लैक हो रहा है। इसलिए, आप ऐसा कोई उपाय निकालें जिससे ब्लैक रुक सके और जो वास्तविक उपभोक्ता हैं उनको सही मूल्य पर स्कूटर मिल सके। कांस्टीट्यूशन के प्रि-एम्बल में भी चेंज कर दिया कि हम समाजवादी हैं। लेकिन, आप प्राईवेट कम्पनीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। यह समाजवाद की दिशा में प्रगति है या प्रगतिवाद की दिशा में। यह समझ में नहीं आता कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इस प्रकार जो बड़ी इन्डस्ट्रीज़ हैं, वे पब्लिक सेक्टर में एस्टेबलिश होनी चाहिए। लेकिन, पता नहीं आप क्यों प्राईवेट कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं? देश को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी: हमारे माननीय सदस्य, श्री सिंह साहब बहुत गम्भीर व्यक्ति हैं। पहले तो इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने गम्भीरता से ही सारे प्रश्न उठाए। यह सदन भी और माननीय सदस्य भी जानते हैं कि स्कूटर्स इंडिया पहले ही पब्लिक सैक्टर में कार्य कर रहा है। उन्होंने सेन्टो स्कूटर निकाला है और पांच करोड़ से अधिक रुपये जमा किए हैं। एक लाख से अधिक सेन्टो के नाम पर स्कूटर बुक हुए हैं। हमें आशा है कि इस स्कूटर का भी ज्यादा प्रचार होगा। जहां तक और पब्लिक सेक्टर का सवाल है, इस पर विचार करेंगे। जैसे लोहिया को पिआगो स्कूटर का लाइसेंस दिया है उसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश की इन्डस्ट्रीय डवलपमेंट कारपोरेशन को भी पिआगो का लाइसेंस दिया है। सिंह साहब का भावात्मक तारतम्य हमारे साथ अधिक जुड़ता है। बजाज स्कूटर की भी मांग बहुत ज्यादा है। इसकी भी दस-दस साल तक मांग थी। इसलिए, हमने सोचा कि इसको लिबरेलाइज़ किया जाना चाहिए ताकि लोग आगे आएं। जब मैंने एक बजे के करीब लिस्ट पढ़ी तो उसमें देखा कि हमने कितने लाइसेंस अलग-अलग पार्टियों को दिए हैं ताकि फ्यूअल एफिशियन्ट आटोमोटिव इन्डस्ट्री हमारे यहां हो और फ्यूअल एफिशियन्ट टू-व्हीलर इन्डस्ट्री यहां शुरू हो सके। अगर अच्छा कोलेबोरेशन मिलता है तो उसके लिए हमने लैटर आफ इन्टेंट भी दिए हैं। उसमें से एक लोहिया मशीन्ज़ भी है।

लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही तेज़ निकले हैं। एडवर्टिजमेंट वगैरह करके ये आगे निकल गए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था और शायद इनको

भी नहीं था कि इतनी ज्यादा अर्जियां आ जाएंगी वैस्पा के नाम पर और जिनके साथ इनका कोलेबोरेशन हुआ है उसकी वजह से। इससे शायद यह साबित होता है कि कंज्यूमर फारेन ब्रांड अच्छा मिले तो उसकी ओर अधिक आकर्षित होता है। सैंटो का नाम वैस्पा के मुकाबले में उतना नहीं चल पाया है। वैस्पा नाम चल पड़ा है। हांडा का नाम भी है। ये पहले से चले हुए हैं। घड़ियों में भी ऐसा होता है। सैनियो का नाम, सीको का नाम आप लें। उन नामों की ओर लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं। यहां भी इतना ज्यादा डिपाजिट हो जाएगा, इसका अन्दाज़ा उनको भी शायद नहीं था। पहले से कौन बता सकता था कि केवल विज्ञापन छापने से इतनी अधिक मांग हो जाएगी? यह कहना बहुत मुश्किल था।

मैं माननीय सदस्य की एक बात सही मानता हूं। इन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ स्पैकुलेटर्ज ने लाटरी की तरह से ही एक ही घर में चार पांच नामों से रुपया जमा कर दिया हो। उनको इसकी व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है—

MR. DEPUTY-SPEAKER : There is a possibility of black money being converted into white and deposited in such industry. That possibility is there.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not attributing any motive to anybody. In such transactions, when the building is not ready and still he advertises and gets Rs. 500/- from every person and 21 lakh people applied and deposited Rs. 105 crores, there is every possibility of black money being converted into white. That is my impression about it.

(*Interruptions*)

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : Out of 21 lakh depositors, I cannot rule out any such possibility, I cannot vouchsafe for all the 21 lakh depositors.

(*Interruptions*)

और जगह भी है। यहां भी है। मैं मना नहीं करता हूं। यह हो सकता है कि कुछ लोगों ने एक ही घर के चार-पांच लोगों के नाम से पैसा जमा कराया हो इस उम्मीद में कि एक तो जल्दी आ जाएगा। इसलिए 21 लाख की जो सूची है वह वास्तविक कंज्यूमर्स की ही सूची हो यह मैं नहीं कहता हूं। ट्रकों में, कारों में भी ऐसा ही होता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The total amount collected is Rs. 105 crores.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not giving any judgement. I am only suggesting.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : I have already accounted for all that money. It has been deposited in public sector undertakings, with public sector banks, with well known private sector companies. I have already mentioned that.

कीमत का जहां तक सवाल है।

श्री मनीराम बागड़ी : डिप्टी स्पीकर ने ब्लैक मनी के बारे में जो कहा है उसका जवाब दें।

MR. DEPUTY-SPEAKER : He has already given.

श्री नारायण दत्त तिवारी : डिप्टी स्पीकर की बात का जवाब नहीं दिया जाता है। माननीय सदस्य के सवाल का मुझे जवाब देना है, उनका नहीं। मैंने बताया है कि 21 लाख ने रुपया जमा कराया है। एक केस भी ब्लैक मनी का केस इस में नहीं है, यह कहना मेरे लिए कठिन है। यह मैं कैसे कह सकता हूं कि सब ठीक है। मैं इस में उलझना नहीं चाहता। जैसे आप से उलझना नहीं चाहता वैसे उनसे भी उलझना नहीं चाहता।

**Not recorded.

आपका भी मैं आदर करता हूं, उनका भी करता हूं। बहुत सी बातों का जवाब नहीं दिया जाता है। जब नहीं दिया जाता है तो उसी में जवाब आ जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have only said that there is every possibility.

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक कीमत का सवाल है, एक्साइज़ ड्यूटी क्या होगी, सेल्ज़ टैक्स क्या होगा—अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेल्ज़ टैक्स है। इस वास्ते इस समय कीमत बताना कठिन है। कम्पनी वालों ने कहा है कि नौ और दस हज़ार के बीच कीमत आएगी। यह उनका अंदाजा है। अत: मैं कीमत की गलत खबर दूं तो मैं जिम्मेदार होऊंगा। इसलिए गलत बात मैं कैसे कहूं। मैं कह सकता हूं कि कीमत के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 9, 10 हजार रु० के बीच कीमत होगी ऐसा बताया गया है।

ऐक्सपेंशन का जहां तक सवाल है यह बात सही है कि उन्होंने अर्जी दी है। उनका कहना है कि स्कूटर की माँग ज्यादा है हम 1 लाख से ज्यादा मैनुफैक्चर करेंगे, यह इजाजत मांगी है। लेकिन जैसा मैंने कहा एक कमेटी इस पर विचार कर रही है। यह मामला अभी हमारे स्तर पर नहीं आया है, हमारे पास नहीं आया है। उनसे कहा गया है कि जब तक आपका प्रोडक्शन न हो तब तक हम इस संबंध में कैसे विचार करें। वह कहते हैं कि 4 लाख किया जाय। अर्जी एक्सपेंशन की जरूर आई है इस बारे में इकौनामिक टाइम्स की खबर और आपकी इत्तिला सही है।

तो मैं आग्रह करूंगा जब हमने एक समिति बना दी है और इस संबंध में अगर कोई गलती होगी तो यह काम कंपनी ऐफ़यर्स विभाग का है वह देखें कि डिपोजिट्स के बारे में गड़बड़ी हो रही है कि नहीं। और कंपनी विभाग इस बारे में सतर्क है और उन्होंने कार्यवाही भी की है। मेरा निवेदन है कि हजारों, सैकड़ों लाइसेंसेज़ दिये जाते हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम राज्य सरकारों का होता है। कई बार लैटर आफ़ इटेंट देने की वह सारी जिम्मेदारी हमारी ही नहीं है, राज्य सरकारों की भी है, कंपनी ऐफयर्स और इकौनौमिक ऐफयर्स आदि विभागों की भी है। जहां तक हमारे विभाग का प्रश्न है हमने पूरा प्रयास किया है कि एक तरफ औद्योगीकरण हो, स्कूटरों की आवश्यकता है वह पूरी हो और उसके क्रियान्वयन में कोई बाधा न हो, और स्कूटर मार्केट में जल्दी आये यह भी हमारा प्रयास है।

श्री बी० डी० सिंह : जो कमेटी आपने बनाई है उसके टर्म्स आफ़ रेफरेंस क्या है? और जो कंपनी डिपोज़िट रूल्स हैं···

SHRI NARAYAN DATT TIWARI : "to go into the question of obtaining of deposits by companies as advances against bookings made by them and to make recommendations to the Government in the matter including suggesting any guidelines in this behalf."

श्री बी० डी० सिंह : 1975 के जो कंपनी डिपोज़िट रूल्स हैं उसमें खासियां लगती हैं। तो आप जुडिशियल इनक्वायरी क्यों नहीं बैठाते?

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी की ओर से जो उत्तर आया है और हमारे माननीय सदस्य ने जो मंत्री जी से जानकारी चाही है दोनों के बीच में इतनी खाई रही है कि मैं और भी उलझन में पड़ गया कि कितना ज्यादा पूछूं।

मैं तो यह समझता था कि उद्योग मंत्री जी हमारे देश की जनता के हितों का ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात जो उत्तर में आयी है उससे मालूम होता है कि केवल पूंजीपतियों के और कंपनी के हितों का मंत्री जी को ध्यान है, देश की जनता के हित का नहीं है। और मंत्री जी आज उद्योगपतियों के वकील की हैसियत से मालूम हो रहे हैं, उद्योगपतियों के संतरी की हैसियत से उनकी रक्षा कर रहे हैं, जनता के प्रतिनिधि के रूप में रक्षा नहीं हो पा रही है।

MR. DEPUTY SPEAKER : He is keeping the interests of capitalism or capitalists. You are keeping the interests of the labour. Both must join together.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : पहली बात यह है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो पब्लिक अन्डरटेकिंग है वह 5 करोड़ रु० की लागत से शुरू हुई थी और करीब 35 करोड़ का उसमें घाटा है। उसकी कैपेसिटी 1 लाख स्कूटर बनाने की है, लेकिन 15, 20 हजार ही बन रहे हैं। क्या आपने लाइसेंस देते वक्त इस बात का ध्यान रखा, और आपने उस कंपनी को जो लाइसेंस दे दिया और जो ऐडवांस अनुमति दे दी तो मैं कहूंगा कि उसको ऐडवांस मनी न कहा जाय, उसकी डैफीनीशन बदल कर लूट मनी, फ्रौड या चीट मनी कहा जाय। उस पर मैं बाद में आऊंगा कि कौन-कौन जिम्मेदार हैं ?

पहले एक तरीका था कि जब स्कूटर का बुकिंग होता था तो पोस्ट आफिस में पैसा जमा होता था। पोस्ट आफिस सरकारी संस्था है, उसमें पैसे की भी सुरक्षा होती थी और पैसे का जनहित में प्रयोग होता था। उसका ब्याज लोगों को मिलता था, उसमें गड़बड़ नहीं होती थी और कस्टमर्स को उसमें धोखा नहीं होता था। लेकिन आपने स्कूटर कंपनी को स्वतः पैसा इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया और उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बीच में बहुत बड़ा अन्तर है। यह जानकारी मिली है कि वह लोगों को 7 और 9 परसेंट का ब्याज देंगे और वह खुद 18 से लेकर 25 परसेंट तक इन्टरेस्ट ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा फर्क है। यह इन्टरेस्ट 21 साल में कितना हो जायेगा ? अगर यह कंपनी सही सलामत काम करती रहे तो 21 साल में सारे स्कूटर बनाकर अपनी लायब्लिटी पूरी कर लेगी।

जब आपने इसको लाइसेंस दिया, शेयर कैपिटल इकट्टा करने की और डिबैन्चर्स मनी डिमांड करने की और एडवांस मनी, जिसको मैं आपसे चीट मनी या फ्राड मनी की डैफिनिशन चाहता हूं, उसकी अनुमति आपने दी तो क्या आपने इसकी जानकारी की कि उस कंपनी के जो स्वामी हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, उनकी कितनी कैपिटल पहले थी, उसकी कितनी प्रापर्टी थी, कितना कर्जा उस पर था, कितनी लायब्लिटीज थीं कितना प्राफिट या घाटा चल रहा था और सरकार का उस पर कितना कर्जा था ? क्या इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने लाइसेंस दिया ? क्या आपने यह सोचा कि जो कंपनी इस तरह की लूट मचा रही है, सबको पता लग गया था इसके बारे में कि करोड़ों-करोड़ों और अरबों-अरबों रुपये की लूट इसके नाम से हो रही है, कुछ लोग यह भी कहते हैं, हमको भी इसकी जानकारी दी गई है कि कोई इटली की कंपनी जो स्कूटर बनाने के काम में लगी है, उसने **उनसे बैठकर, वहां कुछ अधिकारी गए और उन्होंने स्वयं बातचीत की,

DR. KRUPASINDHU BHOI (Sambalpur) : Sir, I take strong exception to this. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the records. I have said that I will go through the records if anything has been mentioned. (*Interruptions*) I will go through it. This problem would not have arisen if we followed the rules. The rules are very clear. The Member who raises the Calling Attention whose name is taken by the ballot only puts one question. Shri Kashyap only can put the question.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Why Shri Kashyap only ? Why not others ? (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : His name is there. I say that if we conduct the delibera-

**Not recorded.

tions according to the rules, nothing will happen. Therefore, the others will please sit down. (*Interruptions*) This is not the way that the calling attention is to be conducted.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : Sir, he has raised a point of order. Give your ruling.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No point of order.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : He has raised a point of order. (*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please don't record anything else other than what Mr. Kashyap says. I am not going to permit. Otherwise I will go to the next subject. You are not dealing with this according to rules. Mr. Kashyap, please conclude. We have taken more than two hours.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shall I read the rules to you ? All of you are very learned and experienced Members. You must help the Chair to conduct the business of the House according to the Agenda.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Sir, I want one clarification.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Whenever you want to speak about the rule, you should get up and ask for my permission. I am not giving you permission now.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : 'Calling Attention' should not take more than half-an-hour. Now, we have taken two-and-half hours. Each Member has taken more than 30 minutes.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jaipal Singh Kashyap, please conclude. There is another important item in the agenda. There is a discussion to be taken up under Rule 193.

(*Interruptions*)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : उपाध्यक्ष, महोदय, मेरा स्कूटर इस दलदल में फंस गया है। उसको निकलवा दीजिए।

इटली से स्कूटर मंगाए गए थे। क्या इटली से फिर और स्कूटर मंगाए गए और उसके बाद इस कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कहा कि यह स्कूटर इस लायक नहीं है कि हम हिन्दुस्तान में उसको डिस्ट्रब्यूट कर सकें ?

इस कंपनी ने स्कूटर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देश में कितनी एजेन्सीज़ दी हैं और उनसे कितना रुपया लिया गया है। जहां तक हम लोगों को जानकारी है, हर एजेन्सी से चार लाख रुपया एडवांस मनी के रूप में लिया गया है और देश में 250, 300 एजेन्सीज़ की व्यवस्था की गई है।

अगर दिल्ली में कुछ अधिकारियों ने यहां पर** किसी व्यक्ति के साथ बैठकर इस सिलसिले में बात की है, तो यह कहना अनपार्लियामेंटरी नहीं हो सकता है। इसका उत्तर आना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य मेरे पड़ोसी हैं और मैं उन्हें जानता भी हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा यह दायित्व है कि जितनी जानकारी मेरे पास है, उसके आधार पर मनसा वाचा कर्मणा प्रश्नों का सही उत्तर दूं। वह जानकारी थोड़ी भी हो सकती है और कभी कभी उस जानकारी को सही भी करना पड़ता है। लेकिन मेरा आग्रह है कि इस सम्बन्ध में किसी की वकालत करने का प्रश्न नहीं है।

**Not recorded.

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनमें से बहुतों का उत्तर दिया जा चुका है। उन्होंने कहा है कि रुपया पोस्ट आफिस में जमा होना चाहिए। यह ठीक है कि पहले बहुत से डिपाज़िटर्ज़ पोस्ट आफिस में जमा किया करते थे। कंपनी डिपाजिट रूल्ज के अनुसार यह कंपनी का आप्शन है कि वह पोस्ट आफ़िस में जमा कराए, बैंक में जमा कराए या कंपनी में जमा कराए। ये रूल आज के नहीं, पहले के हैं। इसमें संदेह नहीं कि अच्छा यही है कि पोस्ट आफिस में जमा किया जाए। लेकिन यह आप्शन हमारे पास नहीं है कि हम तय करें कि कहां जमा करें। यह कंपनी पर है कि वह किस प्रकार डिपाज़िट कराती है। कमेटी इसपर भी विचार करेगी कि डिपाजिट का आकार प्रकार क्या हो और वह किस प्रकार जमा हो, आदि।

जहां तक एजेन्सीज वगैरह का सवाल है, मैं कंपनी की ओर से नहीं बोल रहा हूं, मैं शासन की ओर से बोल रहा हूं, इसलिए यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि कंपनी का कितना बड़ा काम है और उसने कितनी ऐजेन्सीज दी हैं। उसका उल्लेख भी प्रस्ताव में नहीं है।

जहां तक इसमें किसी परिवार का संबंध है, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दबाव या सिफारिश नहीं की गई है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। उनका यह आरोप निराधार है। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य को इस प्रकार का आरोप लगाना उनको शोभा नहीं देता है।

जहां तक स्कूटर का सवाल है, स्कूटर टेस्टिंग के लिए यहां आते हैं, भारत की स्थिति को देखते हुए यह जानकारी आवश्यक है। स्कूटर जरूर मंगवाये होंगे। मुझे उम्मीद है, मैंने उनकी तमाम बातों का उत्तर दे दिया है। इस संबंध में कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तो विचार हो जाएगा।

14.56 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-fifth Report

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH): I beg to move:

> "That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 3rd May, 1983."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved.

> "That this House do agree with the Forty-fifth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 3rd May, 1983."

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): I beg to move:

> "That in the Motion,
>
> add at the end—
>
> "subject to modification—
>
> that the time recommended for discussion on Resolution regarding National Health Policy be increased by 2 hours."

Sir, I feel that after a very long time we are going to have a discussion on National Health Policy and there are many aspects of it which need to be discussed in great detail, and they have allotted only four hours for this. This time is hopelessly inadequate for such an important subject, particularly in the context of the 1981 census.

In this connection, I would like to give you an illustration what kinds of problems people are facing. One of the important thing for maintaining health of the nation is regular check-up; that means having X-ray of chest and other parts of the body, etc. so that one has a clear idea of one's health.